बुन्देलखण्ड की

जल सहेलियां

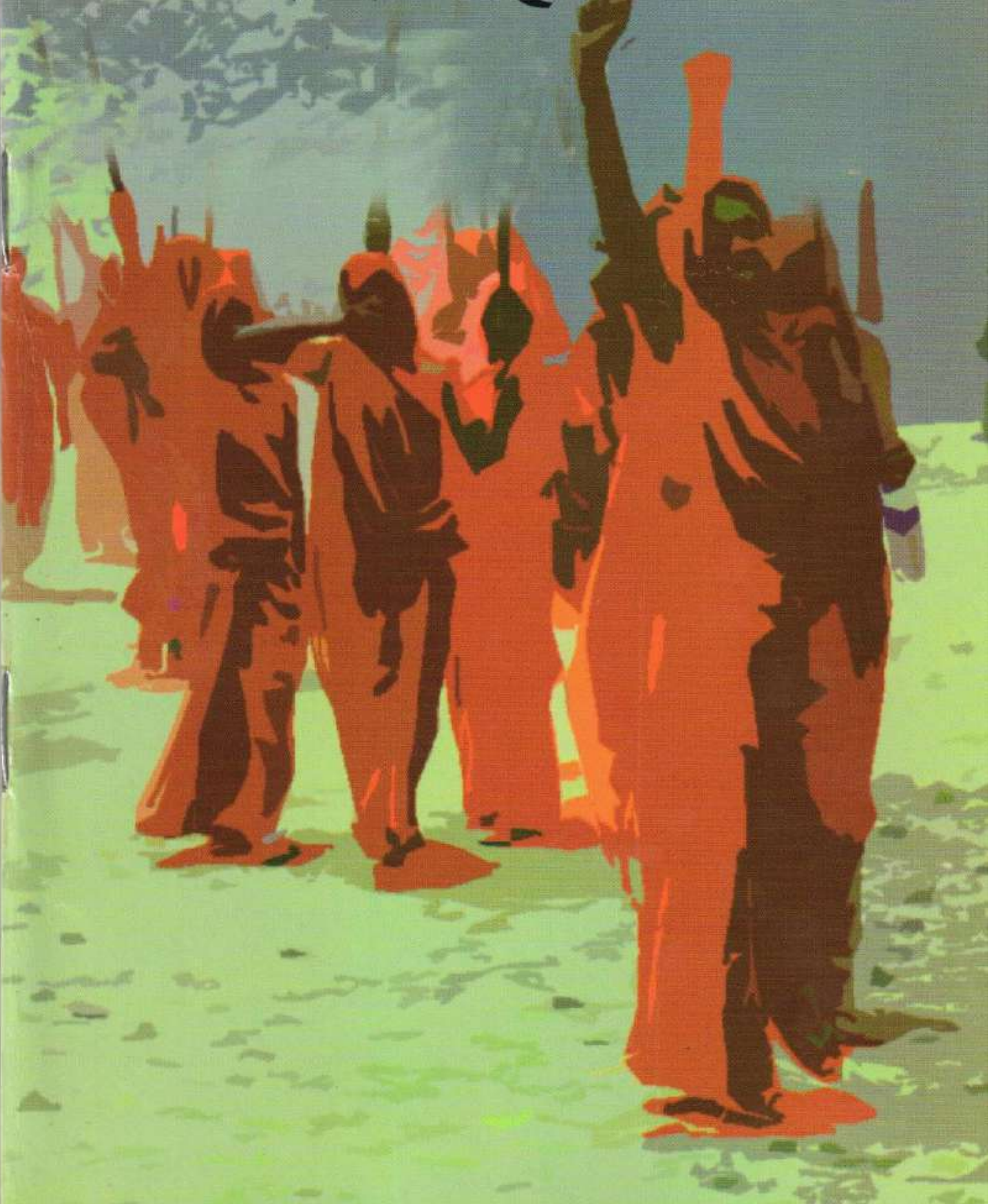

बुन्देलखण्ड की जल सहेलियां

Parmarth Samaj Sevi Sansthan
880, Shivaji Nagar, Behind Bharat
Traders, Jhansi-284001 (U.P.)

जल सहेलियों के लिए

टकराना हमको आता है।
इन सूखे खेत पहाड़ों से।।
इन पथरीली चट्टानों से।
इस जीवन की चट्टानों सें।।
टकराना हमको आता है।
टकराना हमको आता है।।

जीवन तो रोज चुनौती है।
हमकों जीते ही जाना है।।
हो बन्धन चाहे जैसा भी
उसे तोड़ के आगे आना है
इस बंजर धरती पे हमको
एक उपवन नया बनाना है
इन उबड़-खाबड़ रास्तों पर
चलना हमको भी आता है
टकराना हमको आता है

एक भागीरथ से किस्सों में
गंगा धरती पे लाये थे
हम आज के दौर की नारी हैं
इस बीहड़ की चिन्गारी है
इस बहरी -गूगीं सत्ता को
बदलाव का गीत सुनाएगें
हमें सूखे खेतो के आचल में
हरियाली भरना आता है
टकराना हमको आता है।।

दो शब्द

बुन्देलखण्ड अपनी बनावट प्राकृतिक स्थितियों एवं पिछड़ेपन के कारण उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में अलग -अलग पड़ा हुआ लगता हैं। आंकड़े बतातें हैं कि बुन्देलखण्ड की लगभग 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करते हुये परमार्थ समाजसेवी संगठन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और विगत वर्षो से सामाजिक संगठन के रूप में सक्रिय रहते हुये महत्वपूर्ण कार्य किया है। सामन्तवाद और पित्रसत्ता की हनक वाले व्यवस्था में परिवर्तन और अधिकारों की बात करना व्यवहारिक दृष्टि से एक कठिन कार्य हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर समुदाय के हितों एवं अधिकारों की लड़ाई को परमार्थ समाजसेवी संगठन ने नए आयाम दिये है। इसी दशा में महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं परिवर्तन में भागीदार बनाने हेतु महिलाओं का पानी पर प्रथम अधिकार अभियान और 'जल सहेली' अभियान एवं महत्वपूर्ण कदम हैं। बुन्देलखण्ड के जालौन, हमीरपुर व ललितपुर जनपदों में यूरोपियन यूनियन के सहयोग से प्रायोगिक तौर पर चलाई जा रही इस परियोजना ने पिछले डेढ़ वर्षो में न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है बल्कि वे अब इस समूची लड़ाई का नेतृत्व भी कर रही है।

हमें आशा ही नही पूरा विश्वास है कि परमार्थ की इस पहल को समाज और सरकार का समर्थन मिलता रहेगा जिससे जल सहेलियॉ अपने सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकेगी।

संजय सिंह

सचिव परमार्थ समाज सेवी संस्थान

बुंदेलखंड का नाम आते ही एक विपदाग्रस्त पिछड़े क्षेत्र कि तस्वीर सामने आती है. एक ऐसा क्षेत्र जो नदियों की धाराओ के बाद भी सूखा है, जहाँ नदियों कि कलकल कि जगह उसके पेट में छुपे हुए पत्थर दीखते हैं , जहा अपार खनिज सम्पदा के भंडार होने के बाद भी गरीबी के दृश्य आम हैं. जहाँ सामंतशाही के अवशेष अभी भी अपनी ताकत को खड़ा करने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं. जहा के बीहड़ बागियों की कई रक्तरंजित कहानियां अपने अंदर समेटे हैं. आल्हा उदल की ऐतिहासिक कथाओं को गाते हुए लोग है तो सर पर मटकियों में पानी लाने जाती हुयी औरतो और बच्चियों कि लंबी कतारें भी हैं।

जलवायु के शुष्क किरदार ने बुंदेलखंड के नसीब में जिंदगी के लिये हर समय जद्दोजहद की इबारत लिख दी है। यह दूसरी बात है कि बुंदेलों ने संघर्ष भरी जिंदगी को कभी अभिशाप के रूप में नहीं लिया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को कुदरत का नायाब उपहार मानकर जिजीविषा को इसकी सान पर चढ़ाया जिससे हर मुसीबत के तोड़ का मंत्र साधने की कला उनमें आ गयी है। पानी न होते हुए भी बुंदेले इतने पानीदार बने कि उनकी शौर्य गाथा देश के कोने-कोने में गायी जाती है।

बुंदेलखंड में जब बेहतर बारिश होती है तो औसतन 950 मिमी पानी साल में गिरता है लेकिन हर तीन साल में सूखा यहां की अनिवार्य नियति है। इस कारण 10 वर्ष की बारिश के आंकड़े जोड़कर औसत निकाला जाये तो बारिश 500 मिमी प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं रह जाती। उस पर तुर्रा यह कि यहां भू संरचना बेहद जटिल है। नीचे ग्रेनाइट, चूना की परतें व पथरीली चट्टान होने के कारण धरती बहुत ज्यादा पानी नहीं सोख पाती। उधर ऊंची नीची जमीन के कारण बने नालों से

बरसाती पानी का ज्यादातर हिस्सा बहकर नदियों में चला जाता है। यहां न पीने के लिये पानी रह जाता है न सिंचाई के लिये। पानी यहां के जनजीवन के लिये कितना कीमती समझा जाता है इसकी बानगी है यहां की महिलाओं में कही जाने वाली यह बहुचर्चित कहावत खसम मर जाये पर गगरी न फूटे।

सदियों से सूखा

वर्तमान शताब्दी के पहले दशक में बुंदेलखंड में 8 वर्ष सूखा का दौर रहा। इससे जो तबाही मची उसके कारण यह इलाका सारे देश में सुर्खियों में छा गया लेकिन सूखा और अकाल की स्थितियां तो यहां का जनजीवन सदियों से झेल रहा है। मुहम्मद बिन कासिम जब हिन्दुस्तान आया था उस समय बुंदेलखंड जबर्दस्त सूखे की गिरफ्त में होने का जिक्र इतिहास के पन्नों में पढने को मिलता है। अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम होने के बाद तो सूखे का लम्बा दौर रहा। 1809-10 में सूखे के कारण घोर अकाल पड़ा। 1867 से 1892 तक 25 वर्ष लगातार सूखा के कारण हाहाकार मचा रहा। आजादी के बाद भी 60 के दशक में बुंदेलखंड ने भीषण सूखा झेला। अब इसकी पुनरावृत्ति पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गयी है। बिन पानी सब सून की कहावत को ध्यान में रखा जाये तो समझा जा सकता है कि पानी का अभाव यहां जीवन की परिस्थितियों को कठिन बनाये रखता है।

पानी इस इलाके कि सबसे बड़ी त्रासदी है. पानी यहाँ के सामंतो के शोषण का यन्त्र है और पानी ही यहाँ किस्से और कहानियों का केंद्र है. बुंदेलखंड कि सबसे प्रचलित कहावतों में से एक है जिसमे कहा गया है " गगरी न फूटे खसम मर

जाए" ये शब्द यहाँ कि त्रासदी को सामने लाने के लिए सबसे सटीक उदहारण है.

महिलायें सर्वाधिक पीडित

पानी के संकट से सबसे ज्यादा पीडित महिलाओं को होना पड़ता है जो गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाये जैसी कहावतों से स्वयंसिद्ध हैं। पूरे बुंदेलखंड में कई सौ मीटर दूर से गगरी सिर पर रखे दिन भर आती जाती महिलाओं की कतारें दिखने का नजारा आम है। उन्हें इस संकट का दंश कई रूप में झेलना पड़ता है। दिन चढने के पहले ही पानी भरने के श्रम साध्य काम में उन्हें जुट जाना पड़ता है। आधा दिन इसी मशक्कत में गुजर जाता है। इसके बाद वे देर से खाना पकाती हैं तो घर में कलह के दौरान सतायी जाती हैं। श्रम और अत्यधिक समय की बर्बादी का उन्हें कोई मूल्य नहीं मिलता। दूसरी ओर प्रत्यक्ष आमदनी न कर पाने से उनके साथ परिवार में भेदभाव होता है। किसी भी फैसले में उनके परामर्श और सहमति की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

महिलाओं के इस दर्द को परमार्थ स्वयंसेवी संस्था ने महसूस किया और इसका प्रतिफल पानी पर महिलाओं की पहली हकदारी के अभियान के रूप में सामने आया।

बुंदेलखंड में पुरुष प्रभुत्व और सामंतवादी व्यवस्थाओं की विरासत अभी भी कायम है जिसके कारण आधुनिक प्रगति के रास्ते पर यहां पैरों में बेडियां सी पड़ी हुई हैं। महिलाओं की पानी पर प्रथम हकदारी परियोजना का यहां संचालन कई दृष्टियों से क्रांतिकारी कार्रवाई की तरह है। जब महिलायें पानी के लिये सबसे ज्यादा सतायी होती हैं तो पानी की खोज और प्रबंधन के आंदोलन की कुलबुलाहट पैदा करने से जिस उमंग के उनमें संचार की आशा है वह फलीभूत होगी तो ज्यादा सार्थक

परिणाम सामने आयेंगे। दूसरे इस अभियान में उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता को पहचानने का अवसर मिलेगा जिससे सामाजिक जड़ता टूटेगी। परियोजना में दलित, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर हरावल दस्ता बनाने की रणनीति की गयी ताकि वंचित तबकों में नयी चेतना, सक्रियता और आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सके।

उपेक्षा की भेंट चढ़े तालाब

बुंदेलखंड में जल प्रबंधन पूरी तरह समुदाय के हाथों से संचालित होता था। आजादी के बाद वोटों के लालच में सरकार ने लोगों के लिये पानी की व्यवस्था मुफ्त में करने का काम अपने हाथ में ले लिया। गांव-गांव में इंडिया मार्का हैंडपंप लगने शुरू हुए तो तालाबों की उपेक्षा शुरू हो गयी। तालाब भरने के लिये बनायी गयी गूलें पाट दी गयीं। गर्द उड़ाते तालाबों को पाट कर लोगों ने उन पर कब्जे कर लिये। बुंदेलखंड के लगभग 6 हजार तालाबों में ज्यादातर खत्म हो चुके हैं। सदानीरा 1600 बड़े तालाबों में मात्र 40 शेष रह गये हैं। दूसरी ओर बड़ी सिंचाई व पेयजल परियोजनाओं के कारण भूमिगत जल भंडार लगातार रीत रहा है। तालाब न रह जाने से वाटर रीचार्ज की प्रक्रिया भी ठप पड़ गयी है। सन 2000 से 2008 तक पड़े सूखे के समय इसके भयावह परिणाम सामने आये। खेती न हो पाने से लोग जीविका से हाथ धो बैठे। हजारों लोग गांव-गांव से पलायन करके सुदूर महानगरों में मजदूरी करने चले गये। सैकड़ों किसानों, मजदूरों ने भुखमरी जैसे हालातों के कारण आत्महत्या कर ली। इस विभीषिका का सामना करने के बाद जल प्रबंधन की परंपरागत व्यवस्था का स्मरण लोगों को फिर होने लगा।

बार बार आने वाले सूखे कि मार ने यहाँ के प्राचीन राजाओं को भी ब्यथित किया था इसलिए बारहवीं षताब्दी के चंदेल राजाओं ने इस इलाके में सैकड़ो तालाबो का निर्माण कराया था मगर वक्त कि मार और नीतियों कि कमी ने इन तालाबो का अस्तित्व मिटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी.

पिछले वर्शों 2006-2007 के सूखे ने इस इलाके के विकास को दशकों पीछे कर दिया. लगातार आठ वर्षों तक इस सूखे का प्रकोप रहा. नदिया सूखी, कूएं सूखे और तालाब भी सूखे. ऐसे में इस इलाके के लोग बड़ी संख्या में पलायन कर गए. गांव के गाँव खली हुए तो वही किसानो ने आत्महत्याएं भी की. पूरा बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सात जिलों झांसी, महोबा ललितपुर, हमीरपुर बांदा चित्रकूट और जालौन और मध्य प्रदेश के जिलों छतरपुर, टीकमगढ़ दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड को मिलाकर बना है। बुन्देलखण्ड का पठार प्राकेम्बियन युग का है। पत्थर, ज्वालामुखी और रवेदार चट्टानो से बना है इसमें नीस और ग्रेनाइट की अधिकता पाई जाती है। इस पठार की समुद्रतल से ऊचाई 150 मीटर उत्तर और 400 मीटर दक्षिण है। छोटी पहाड़ियां भी इस क्षेत्र में है जिनका ढाल दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। बुन्देलखण्ड का पठार तीन ओर से अर्धचन्द्रकार, पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, नरहर स्कार्प तथा चंदेरी पार से घिरा है। इस पठार की साधारण ढाल उत्तर की ओर है। यहॉ उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदियॉ बेतवा और धसान हैं जो यमुना की सहायक नदियॉ है। बुन्देलखण्ड का पठार मुख्यतः मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों में विस्तृत है। इसी क्षेत्र की अन्य प्रमुख नदियॉ चम्बल, केन सिन्धु, और सोन नदियों

की प्रकृति भी पर्वतीय है क्योकि यह पर्वतों से जम्मी और पर्वतों के साथ ही अपनी जीवन यात्रा करती है। ग्रीष्म ऋतु में नाले के रूप में ये नदियॉ सूख जाती है किन्तु बरसात में यही नदियॉ अपने पाट और घाट को आधीन विस्तार देती हैं। बांढ़ के कारण जन-धन की हानि का यें सबक बनती हैं।
बुन्देलखण्ड की बनावट और प्राकृतिक स्थितियॉ बुन्देलखण्ड के जीवन को अधिक विषम बना देती है। ऐतिहासिक रूप से यह भू-भाग कम जनसख्या धनत्व वाला रहा है। इसका मुख्य कारण अनउपजाऊ कृशि भूमि और अत्यधिक उमस व गर्मी का मौसम माना जाता है। औधौगिक एवं शहरी विकास के पैमाने पर भी यह इलाका पिछड़ा ही माना जाता है। राजनीतिक अस्थिरता और अराजक समाज में भी इस पूरे क्षेत्र को विकास के पैमाने पर नीचे रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड की (कुल सात जिलों) आबादी करोड़ है और जनसंख्या धनत्व प्रति वर्ग कि0मी0 है। इस इलाके की एक (242 प्रति वर्ग किमी से 408 प्रति वर्ग किमी) चौड़ाई पिछड़ी जातियों की है जिनमें से 82 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। अगर आंकड़ों को देखे तो झांसी को छोड़कर इस पूरे क्षेत्र की एक चौथाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। बुंदेलखण्ड के मैदानी भागों मुख्य रूप से जालौन और बॉदा में तुलनात्मक रूप से अधिक जनसंख्या घनत्व है। उत्तरी तथा दक्षिणी पठारी इलाकों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है।
अगर इस क्षेत्र की समस्याओं पर नजर डाले तो गरीबी अशिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याये प्रमुख रूप से उभर कर आती है परन्तु लगातार पॉच वर्षो से पड़ रहे सूखे

और सरकारी अनदेखी की वजह से स्थितियाँ बद से बदत्तर होती जा रही है।

पिछले एक दशक औसत 18-55 में एक ओर जहॅ जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हुई है वही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है महिला साक्षरता की दर औसत प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन प्रतिश ही है। एक ओर जहॅ जनसंख्या के हिसाब में महिलाओं की संख्या पुरूषों से अधिक है वहीं शिक्षा का अभाव उन्ही प्रगति भागीदारी एवं पहुॅच में बाधां बना हुआ हैं। शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अधिक दयनीय है।

ऑकड़े गवाह है कि लगभग 80 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की पहॅुच एवं कृयान्वयन में भी प्रदेश की यह आग अत्यंत पिछड़ा है। सरकारी महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा भी रोजगार की गारन्टी देती है भी वर्तमान में कम कृषि पैदावार घटते प्राकृतिक संसाधन और कम होते जल संसाधनों को संबोधित करने में असमर्थ हैं। उत्तर प्रदेश के 15 जिलो में (जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 जिले शामिल है) एक गैर सरकारी संख्या द्वारा मनरेगा में अनुसूचित जातिध्जाति की भागीदारी सम्बन्धित अध्ययन में पाया गया कि इन योजनाओं में उनकी भागीदारी मात्र 44-64 प्रतिषत है जबकि इनकी आबादी लगभग 80 प्रतिषत है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक रोजगार श्रोतों में लगातार कमी आई जिससे खाद्य सुरक्षा और प्रभावित हुई है। पिछले पॉच दशको से निरन्तर सूखे ने इस पूरे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। सूखे ने यहॉ के विकास पर भी ऋणात्मक प्रभाव डाला है।

बुन्देलखण्ड की अधिकांश आबादी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था खेती और उससे जुड़े रोजगार पर निर्भर है। इनमें से 75 प्रतिशत किसान छोटे और मझोले है और औसत जोत लगभग 2 हेक्टेयर है। उनकी आजीविका परोस या अपरोक्ष रूप से निर्भर है। खेती की बढ़ती लागत, और नई तकनीक ने उनकी स्थिति को ओर विकट बना दिया है। पुराने परम्परागत बीजों के स्थान पर महॅगें हाईब्रिड बीजो का उपयोग होने लगा है। बीजो पर से किसानों का नियन्त्रण निरन्तर कम होता जा रहा है छोटे किसानों की अधिवक्ता एवं संसाधनों की कमी की वजह से किसान कर्ज के जाल में फसता चला जा रहा है। बुंदेलखण्ड में किसान कर्ज के जाल में फसता चला जा रहा है। बुंदेलखण्ड में किसानों की आत्महत्याएं इसका प्रमुख कारण है। एक ऑकड़े के अनुसार बुंदेलखण्ड में पिछले 2-5 सालों में 1400 किसानों ने आत्महत्याये की है। यह सचमुच विस्फोटक स्थिति है।

वर्तमान चुनौतियॉ

विषम आर्थिक सामाजिक स्थितियों से लड़ते हुये आगे बढ़ना बुंदेलखण्डी समाज के लिए एक गम्भीर चुनौती है। खेती, रोजगार , स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों में विषम से विषमतर होती स्थितियों से लड़ाई हर मोर्चे पर लड़नी होगी। सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का जाल तो अवश्य बुन दिया है परन्तु भ्रष्टाचार एसं कुप्रबन्धन ने सच्चाई और ऑकड़ों में भारी अन्तर पैदा कर दिया है। सरकारों के साथ-साथ इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के लिये भी यह एक गम्भीर चुनौती हैं। सिलसिलेवार ढंग से देखे तो चुनौतियॉ निम्न है-

विषम प्रकृतिक एवं भौगोलिक संरचनाः

बुन्देलखण्ड की प्राकृतिक एवं भौगोलिक संरचना उसे उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य क्षेत्रों से भिन्न करती है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र के लिये यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप योजनायें बनाये जाने की आवश्यकता है।

सूखे का इतिहास

पिछले पाँच वर्षो से चले आ रहे सूखे ने इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर भारी आघात किया है। एक ओर जहाँ -यहाँ की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनकी जीविका का आधार मुख्यतः कृषि ही है।, वही दूसरी ओर सूखे एवं समुचित जल प्रबन्धन न होने से दोहरी मार पड़ी है। इन पिरिथितियों ने स्थानीय आबादी के हक और हुकूक दोनो को प्रभावित किया है और उन्हें पलायन के लिये मजबूर किया है। इस पूरी प्रक्रिया में स्त्रियों एवं बच्चों को स्थिति को अत्यंत विषम बना दिया है।

सिंचाई की सुविधाओं का अभाव

बुंदेलखण्ड के किसान मुख्य रूप से रबी की पैदावार पर ही आश्रित रहते हैं और अधिकतम खेतिहर भूमि इसी मौलक में सिंचित हो पाती है। मात्र 20 प्रतिशत खेतिहर भूमि ही खरीफ के मौलक में सिंचित हो पाती है। ऑकड़े बताते है कि सिंचाई

की सुविधाओं के आभाव और कुप्रबन्धन की वजह से 60 प्रतिशत खेती योग्य भूमि असिंचित रह जाती है जिसकी वजह से पूरी की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

हॉलाकि सकल खेतिहर भूमिध्रोपित क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है लेकिन खरीफ के मौसम में 85 प्रतिशत और 55 प्रतिशत भूमि असिंचित ही रह जाती है। खरीफ की फसल मुख्य रूप से बारिश पर ही निर्भर रहती है लेकिन कम वर्षा, भूमि की घटती उपजाऊ क्षमता और वैकल्पिक सिंचाई के साधनो के अभाव ने इस समस्या को और गम्भीर बना दिया है।

कृषि के बदलते तौर तरीके

समय के साथ-साथ बढ़ते बाजारीकरण ने हमारी कृषि और परम्परागत और तरीकों पर व्यापक प्रभाव डाला है। एक ओर जहॉ किसानों का बीजो पर नियन्त्रण खत्म हो रहा है। वही अधकचरी सूचनाओं और अपर्यात तकनीकी जान की वजह से नई तथा कठित नई टेक्नालोजी ग्राह्य नही हो सकी है और किसानो को कर्ज का मकड़जाल में फॅसाती चली जा रही है। एक ओर जहॉ नये बीज और फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता है वहीं आर्थिक रूप से कमजोर छोटे और सीमान्त किसानों (जो कि 80 प्रतिशत है) के लिये यह घाटे का सौदा ही साबित हो रहा है।

पशुपालन और नई चुनौतियॉ

पशुपालन हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक है और बुन्देलखण्ड के सन्दर्भ में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन चारागाहों के सिमटने, सूखे और अन्य स्थानीय कारकों ने समीकरणों को बिगाड़ कर रख दिया है। ऑकड़ों के अनुसार 77-78 में 9-033 हेक्टेयर भूमि चारागाहों के रूप में उपलब्ध थी जो प्रकारान्तर में घटकर आज ही रह गई है।

जल संसाधनों का घटना

एतिहासिक रूप से बुंदेलखण्ड का क्षेत्र अपने तालाबों, बावड़ियों, तालाबों और कुओं से भी जाना जाता है। ये जल स्त्रोत भूजल को रीचार्ज और नियंत्रण में रखा करते थे। और जमीन की नमी को बनाये रखते थे। पोखरो बावडियों और कुओं को बनाना पारस्परिक प्रथायें थी और लोग इन्हें वर्षा के जल संरक्षण, सिंचाई, मनुष्य और पशुओं का पीने के पानी की उपलब्धता के लिये इनका निर्माण कराते थे। यह धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा लगता था। और ऐसा माना जाता था कि इससे पुन्य लाभ होता हैं। परन्तु समय के साथ-साथ स्थितियॉ बदली, सरकारी और समुदायिक अपेक्षाओं के कारण भूजल के स्तर में गिरावट और जमीन का अनउपजाऊ हो जाना नई चुनौतियॉ उत्पन्न कर रहा है। पिछले पॉच सालों के सूखे ने स्थिति को और दयनीय बना दिया है।

वंचित दलित और आदिवासी समाज

बुंदेलखण्ड के दलित और आदिवासी समाज के लोग अत्यंत गरीबी में अपना जीवनयापन करते है। आदिवासियों को ले तो ये लोग परम्परागत रूप् से अपनी आजीविका के लिये जंगलों पर ही निर्भर थे। हालॉकि इनमें से कुछ के पास कुछ भूमि भी है जो कि पथरीले क्षेत्रों में और अनउपजाऊ है और जहॉ सिंचाई की सुविधा नहीं है। जंगलों के कम होते जाने और अपने उत्पादों के लिये बाजार दूर होने के कारण इनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आधे छोटे खेतों में भी वे अपने लिये चार से छः माह की उपज ही ले पाते है जो कि उनके लिये पर्याप्त नही है। इससे पलायन बढ़ा है और जीवन के साथ भुखमरी की स्थिति हमेशा बनी रहती है।

जहां चाह वहां राह

इस परिवेश में प्रकृति की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिये बुंदेलों ने जहां चाह वहां राह का मंत्र आत्मसात किया। अल्प वर्षा में जीवन को संभव बनाने के लिये उन्होंने अपना ज्ञान और कौशल विकसित किया। चंदेलों के समय गांव-गांव में तालाबों की श्रृंखला बनी। कुएं और बावडियों की भरमार हुयी जिससे बूंद-बूंद पानी को संचित किया जा सके। तालाब यहां की संस्कृति का अंग बना दिये गये। कोई पुण्य कार्य करता तो तालाब खुदवाना अनिवार्य होता है, पूर्वजों की स्मृति में तालाब खुदवाये जाते। यहां तक कि पंचायतें अगर गलती पर किसी को दंडित करतीं तो उसमें भी तालाब खुदवाने की सजा का प्रावधान किया जाता। तालाबों में न केवल मवेशियों की प्यास बुझायी जाती बल्कि नहाने, कपड़ा धोने व अन्य सारे दैनिक जीवन के जरूरी काम तालाब से ही निपटाये जाते। कई जगह तो तालाब का पानी इतना स्वच्छ रहता था कि उसे पीने के

लिये भी इस्तेमाल किया जाता था। तालाब जीविका के भी आधार थे। इनमें मत्स्य पालन, सिंघाड़े की पैदावार के साथ-साथ इनके सहारे मूंज व सरपत पर आधारित हस्तशिल्प के कुटीर उधोग भी चलते थे।

तालाबों के लिये ग्रामीण अभियांत्रिकी

तालाब बनाने के लिये कोई इंजीनियर नहीं बुलाया जाता था। सयाने लोग इकट्ठे होते और वही तालाब खोदने का नक्शा तैयार कर लेते थे। अभियांत्रिकी का पूरा कौशल उनके अनुभव में झलकता था। तालाब इस प्रकार बने कि जब एक तालाब भर जाता था उसका अतिरिक्त पानी नालीनुमा नहर के जरिये, नीचे बने दूसरे तालाब में भर जाता। बारिश आने के पहले हर वर्ष श्रमदान करके तालाब की सफाई भी की जाती थी। तालाबों को बुंदेलखंड के जनजीवन की प्राण रेखा कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

महिलाओं का पानी पर प्रथम अधिकार की स्थापना

आंकड़े बताते है कि जहॉ एक ओर महिलाओं को जनसंख्या पुरूषों के मुकाबले अधिक हैं वही स्वास्थ्य शिक्षा और अधिकारो के मामले में वे वंचितों के भी तंत्रिक की श्रेणी में खड़ी है चाहे वह किसी भी समुदाय अथवा वर्ग की हों। जहॉ तक कार्य के बटवारें में उनकी स्थिति व सवाल है उसकी भागीदारी पुरूषों के वर्चस्व वाले खेती के कार्यो में भी महिलाओं का योगदान 70 प्रतिशत तक होता है। ऐसे में यह मानना उचित ही होगा कि किसी भी प्रदान के परिवर्तन के लिये चाहे वह सामाजिक हो,सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो अथवा अधिकारों की

बात हो, महिलाओं से ही शुरूआत करनी होगी। अक्सर यह देखा गया है कि महिलायें जो काम करती है उसमें 80 प्रतिशत तक काम पाने का होता है। इसके अलावा घर में पीने के पानी की व्यवस्था भी महिलाओं के हाथ में ही होती है जो कि सीधा पूरे समुदाय के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र पिछले कई वर्षो से पानी की समस्या से ग्रसित है। सूखे के चलते यहॉ के अधिकर जल स्रोतो गर्मियों में सूख जाते हैं। ऐसे में महिलाओं को पानी की व्यवस्था एक से दो किमी0 तक पैदल चलकर करनी पड़ती है। उसके बाद भी उनको शुद्ध जल उपलब्ध नही हो पाता। जिससे वे कई गम्भीर बीमारियों का शिकार हो जाती है। ऐसे में सोचा गया कि न केवल महिलाओं को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए पानी के संसाधनों पर उनका प्रथम हक हो बल्कि गांव में स्थिति परम्परागत जलस्रोतो के रखरखाव व पानी के संरक्षण व संचयन की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हवाले की जाय। यह सब तभी सम्भव था जब महिलाओं का एक मजबूत संगठन हो जो गांव से लेकर जिला स्तर तक अपनी लड़ाई के लिये पहल कर सके।

परियोजना का कार्यक्षेत्र

बुन्देलखण्ड के जालौन, हमीरपुर व ललितपुर जनपदों में यूरोपियन यूनियन के सहयोग से परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा पानी पर महिलाओं की प्रथम हकदारी परियोजना का संचालन अप्रैल 2011 से किया जा रहा है। जिसमें से जालौन

के माधौगढ़, रामपुरा ब्लाक की 20 ग्राम पंचायत हमीरपुर के सरीला ब्लाक की 20 व ललितपुर के तालबेहट ब्लाक की 20 कुल मिलाकर तीनों जिलों के 60 ग्राम पंचायतों के 96 गांवों में परियोंजना का संचालन किया जा रहा है।

मुख्य उद्द्देश्य

महिलाओं की भागेदारी के साथ जल प्रबंधन के माध्यम से समुदाय के जोखिमध विपन्नता को कम करना।

विशिष्ट उद्द्देश्य

- ❖ समग्र जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से सभी गांवों में स्थायी रूप से पीने के पानी की सुरक्षा सुनिश्चत करना।
- ❖ विकेन्द्रीकरण तथा सामुदायिक जल प्रबंधन के पहल के माध्यम से पानी तथा आजीविका के जुड़ाव में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना।
- ❖ स्थानीय संस्थाओं के विकास तथा क्षमता वृद्धि के माध्यम से महिलाओं के लिए समता व न्याय को हासिल करना।
- ❖ स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा कृषि के लिए पानी के सतत उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करना।
- ❖ स्त्रिलाओं के पैरवी समूह के माध्यम तथा उनके नेतृत्व को बढ़ावा के द्वारा पंचायत में महिलाओं की भागेदारी व निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करना।

परिकल्पना-

अक्सर यह देखा गया है कि हमारे समाज में खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने व जानवरो तक का काम महिलाऐं ही करती हैं इन कामों में से 80 प्रतिशत काम पानी का होता है इसके अलावा घर मे पीने के पानी तक की व्यवस्था करने में महिलाओं की ही मुख्य भूमिका होती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र पिछले कई वर्षो से पानी की समस्या से ग्रसित है। सूखे के चलते यहां के अधिकतर जलस्रोत गर्मियों में सूख जाते है। ऐसे में महिलाओं को पानी की व्यवस्था एक से लेकर दो किमी0 तक पैदल चलकर करनी पड़ती है उसके बाद भी उनको शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिस कारण कई महिलाऐ पेट की खराबी व बच्चादानी में समस्या जैसी गंभीर रोगों का शिकार हो गई हैं। ऐसे में यह परिकल्पना की गई थी कि न केवल महिलाओं को शुद्ध जल उपलाब्ध कराने के लिए पानी के संसाधनों पर उनका प्रथम हक हो बल्कि गांव में स्थित परम्परागत जलस्रोतों के रखरखाव व पानी के संरक्षण व संचयन की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हवाले की जाये। यह सब तभी संभव था जब महिलाओं का एक मजबूत संगठन हो जो गांव से लेकर जिला स्तर तक अपनी लड़ाई के लिए पहल कर सके।

जल सहेली

पानी तथा स्वच्छता के अधिकार, प्राकृतिक जल प्रबंधन महिलाओं का पानी के साथ जुड़ाव कर सामाजिक बदलाव हेतु जल सहेली का चयन कर उनको एक्सपोजर विजिट व तरह-तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार किया गया। इनकी पानी पर

समझ बनाने के लिए संस्थान द्वारा जल पुरूष के नाम से विख्यात राजेन्द्र सिंह के कार्य क्षेत्र भीकमपुरा (अलवर राजस्थान) में महिलाओं को पानी के संरक्षण मॉडल दिखाने के लिए बिजिट कराई गई थी। गॉव की खुली मीटिंग कर अपनी परियोजना के उद्देश्य को गॉव वालों के सामने रखा गया परियोजना क्षेत्र प्रत्येक गांव में एक पानी पंचायत जिसमें 15 से 25 महिलाऐ सदस्य हैं तथा इन्हीं में से ऐसी दो महिलाओं का चयन जल सहेली के रूप में किया गया जो गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहती थी। कुल जल सहेली जालौन में 60 ललितपुर में 64 तथा हमीरपुर में 45 हैं।

हर माह एक बार मीटिंग होती है जिसमें गांव में पानी से सम्बंधति समस्याओं व गांव में कराये जाने वाले अन्य कार्यो पर चर्चा की जाती है। उसी के अनुसार यह महिलाऐं अपना प्लान कर पूरे माह की कार्ययोजना बनाती हैं। पानी की समस्या व पानी के संरक्षण के लिए पंचायत व मनरेगा से काम के लिए ग्राम प्रधान से लेकर जिला प्रशासन तक पहल करती हैं। जल सहेलियों का निर्माण वैसे तो मई 2011 से ही हो गया था लेकिन एक वर्ष उनकी क्षमता वृद्धि कर स्थापित होने में लग गया जिस कारण अभी इनके द्वारा किये गये हस्तक्षेप परिणाम अभी आने शुरू हुए है।

प्रयास

ललितपुर के तालबेहट ब्लाक के वैसे तो 40 गांवों में ही जल स्रोतों के रखरखाव के लिए जल सहेलिया कार्य कर रहीं है लेकिन बुढ़ावनी गांव में इनके हस्तक्षेप एक तालाब का पुनरूद्धार किया जिसमें इस बरसात में काफी पानी भर गया इसके पहले तालाब में कभी पानी इकट्ठा नहीं हो पाया। यहां 11 हैण्डपम्प स्थापित हैं लेकिन गर्मी को मौसम आते-आते 5 हैण्डपम्प पूरी तरह सूख जाते थे लेकिन इस वर्ष तालाब में पानी रहने से एक भी हैण्डपम्प नहीं सूखा। इसके आलावा लालोन, हसऊपुर व सोहापुर गांव की दलित बस्ती में एक भी हैण्डपम्प नहीं था वहां के 105 परिवार पानी की व्यवस्था करने में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देते थे। जल सहेलियो ने तहसील दिवस, उपजिलाधिकारी, जलनिगम के साथ लगातार पहल कर तीनों गांवों की दलित बस्ती में एक-एक हैण्डपम्प की स्थापना करवाई।

हमीरपुर के सरीला ब्लाक गोहली गांव में वैसे तो बहुत बड़ा तालाव बना है लेकिन गांव वालों की नासमझी के कारण इसका कोई उपयोग नहीं था पूरा तालाब कचरा बन गया था जिसका पानी मनुष्यों के लिए तो दूर की बात जानवरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। जल सहेलियों ने बैठक कर निर्णय लिया कि गांव के तालाब का सुन्दरीकरण करना है इसके लिए बजट उपलब्ध नहीं हो पाया तो गांव की महिलाओं ने एक सप्ताह तक खुद ही श्रमदान पर सुन्दरीकरण किया अब इसका पानी नहाने कपड़ा धोने में तो इस्तेमाल हो ही रहा है साथ ही कुओं का जल स्तर भी बढ़ा है। हरसूड़ी गांव में घरों के नलों का पानी बहकर बेकार चले जाने की

प्रथा को रोकते हुए वहां किचिन गार्डन का चलन जिसके तहत गांव में पांच लोंगों ने किचिन गार्डन तैयार की जिससे इन परिवारों को अब हरी सब्जी मुफ्त में उपलब्ध हो रहीं है। वहीं परछा गांव में प्रधान के साथ गठजोड़ कर मनरेगा के तहत प्रस्ताव करवाकर किसानों के खेतों में 1500 मी0 मेड़बंदी का काम भी जल सहेलियों की पहल पर किया गया।

जालौन के रामपुरा ब्लाक के हमीरपुरा गांव में ऊंची नीची पड़ी जमीन को सिंचित करवाने के लिए एक चौकडेम का निर्माण, कस्बा गांव में जिस माइनर में गोद जमा हो जाने से पिछले 10 वर्षो से पानी नहीं आया उसकी सफाई के लिए माधौगढ़ जगम्मनुपर रोड जाम कर प्रशासन से लड़ाई लड़ी और पंचायत से इसकी खुदाई करवाकर खेतों के लिए पानी उपलब्ध करावाया। इसके अलावा मल्हानुपरा गांव के बीहड़ क्षेत्र में पंचायत से मेड़बंधी व गांव के तालाब को श्रमदान के द्वारा गहरीकरण किया।

इसके अलावा तीनों जिलों के प्रत्येक गांव में जल सहेलियां बरसात के पानी की एक-एक बूंद को संरक्षित करने के लिए जल सुरक्षा कार्ययोजना (वाटर सिक्यूरिटी प्लान) का निर्माण कर उसे पंचायत में लागू करवाने के लिए पहल कर रहीं हैं।

ग्राम प्रधान बनी सहयोगी

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सरीला के अर्न्तगत ग्राम परछा बसा है। यह गांव विकास खण्ड सरीला से 11 किमी0

तथा जिला मुख्यालय से 73 किमी0 दूर पर स्थित है। इस गांव में कुल परिवारों की संख्या 363 तथा जनसंख्या 2251 है। जिसमें से 695 अनुसूचित जाति के हैं। इस गांव की ग्राम प्रधान लज्जावती पत्नी शंकर लाल लोधी जाति से थी। जो क्षेत्र की समस्याओं, परम्परागत सोच, क्षेत्र में महिला पंचायत प्रतिनिधियों के घर से न निकलना, पंचायत की भूमिका में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने जैसी मान्यताओं से जुड़ी थी। जबकि गांव की पेयजल की समस्या थी। इस समस्या का असर महिलाओं के स्वास्थ्य तथा बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रहा था। बुन्देलखण्ड में लगातार सूखे व गिरते जल स्तर के कारण गांव के 53 कुंए सूख गये थे। जिससे गांव की सिंचाई आपूर्ति होती थी। जिस कारण गांव न केवल पीने के पानी बल्कि सिंचाई के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। ऐसी स्थिति में परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा पानी पर महिलाओं की प्रथम हकदारी परियोजना के अर्न्तगत दिसम्बर 2011 में संगठन का गठन किया गया। इस संगठन में लज्जावती ने भी सदस्यता ली और वह संगठन की बैठकों में लगातार हिस्सा लेने लगी। तथा संस्था द्वारा आयोजित महिला पंचायत प्रतिनिधियों का पंचायतीराज अधिनियम भूमिका एवं जिम्मेदारी प्रशिक्षण में भाग लिया। इस प्रशिक्षण ने लज्जावती को इतना प्रभावित किया कि प्रशिक्षण के बाद उन्होंने गांव में एक खुली बैठक की जिससे संगठन की अन्य महिलाओं को भी बुलाया गया और गांव की कार्ययोजना में सबसे अधिक कार्य पानी प्रबंधन व उसके संरक्षण के जोड़े गये। जिसमें से ग्रामीणों के खेतों की 250 मीटर मेड़बंधी डल चुकी तथा अन्य कार्य

भी किये जा रहे हैं। इसी दौरान संस्थान द्वारा पानी के प्रति लोगो को जागरूक करने के लिए निकाली गयी पानी अधिकार यात्रा के समापन समारोह की अध्यक्षता की तथा में 350 महिला पुरूषों के बीच पहली बार संबोधित करते हुए गांव में महिलाओं की समस्या का समाधान करने, स्वच्छता व पानी प्रबंधन आदि के कार्यो को हमेशा अपनी पंचायत में प्राथमिकता देने की बात की। जिस गांव की प्रधान कभी घर से नहीं निकली और न ही कभी गांव की समस्याओं को प्राथमिकता दी। लेकिन संगठन के बाद ग्राम प्रधान में आया बदलाव निश्चित रूप से संगठन का ही परिणाम है।

महिलाओं की पहल से मिला खेतों को पानी

जनपद जालौन के विकास खण्ड रामपुरा से 3 किमी0 दूरी पर स्थित है ग्राम पंचायत कस्बा। जो जनपद मुख्यालय से 55 किमी0 दूर है। गांव में 148 परिवार निवास करते है। जिसकी कुल जनसंख्या 783 है। यहां आजीविका का प्रमुख साधन मजदूरी और कृषि है। गांव के पास से निकली नहर में पिछले 3 वर्षो से पानी न आने से 500 बीघा जमीन में कुछ पैदा नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने जिसकी शिकायत कई बार तहसील दिवस में की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीण हार थक कर बैठ गये। इस नहर के पास जिन छोटे किसानों की जमींने थी वह अपनी आजीविका चलाने के लिए बाहर कमाने चले गये। जब इस गांव में अक्टूबर माह

में परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा संगठन का गठन किया गया। इसमें निकलकर आया कि गांव के पास से निकली नहर में पानी न आने से यहां के खेतों में कुछ पैदा नहीं हो रहा है जिस कारण लोगों को अपनी आजीविका चलाने में कठिनाई हो रही है। पानी की समस्या से परेशान महिला पंचायत के सदस्यों ने संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ दिनांक 05 नवम्बर 2011 को ग्राम प्रधान श्री अखिलेश से मिले इस पर प्रधान ने कहा कि माइनर सफाई हेतु मनरेगा में कोई पैसा नहीं है जिस कारण नहर की सफाई हम नहीं करा सकते है। इसको सिंचाई विभाग स्वयं करवायेगा। फिर महिलाओं ने सिंचाई विभाग को प्रार्थना पत्र दिये लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई हार थक कर महिलाओं ने एक दिन पानी पंचायत की बैठक में तय किया कि ऐसे हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों कि हम लोग एक दिन अपनी पानी की समस्या को लेकर रोड जाम कर दें। और उसे तब तक न खोले जब तक हमारी समस्या के समाधान का काई नेता या जिला स्तर का अधिकारी आकर आश्वासन न दे। इसके बाद अपने पूर्व योजना के अनुसार दिनांक 05 दिसम्बर 2011 को माधौगढ़ रामपुरा रोड पर महिलाओं ने जाम लगा दिया। जिसमें गांव की एक सैकड़ा से अधिक महिला पुरूषों के अलावा ब्लाक प्रमुख श्री सुदामा दीक्षित ने भी गांव के लोगों का साथ दिया। जाम लगने से पूरा यातायात प्रभावित हो गया। जाम की सूचना पाकर थानाध्यक्ष रामपुरा ने मौके पर पहुॅचकर जाम खुलवाने की कोशिश की लेकिन वह संगठन की महिलाओं के हौसले को डिगा नहीं सकें जिसमें पुलिस व महिलाओं में जमकर छीना झपटी हुई। पुलिस ने महिलाओं के अभद्रता की। जिसकी ब्लाक

में परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा संगठन का गठन किया गया। इसमें निकलकर आया कि गांव के पास से निकली नहर में पानी न आने से यहां के खेतों में कुछ पैदा नहीं हो रहा है जिस कारण लोगों को अपनी आजीविका चलाने में कठिनाई हो रही है। पानी की समस्या से परेशान महिला पंचायत के सदस्यों ने संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ दिनांक 05 नवम्बर 2011 को ग्राम प्रधान श्री अखिलेश से मिले इस पर प्रधान ने कहा कि माइनर सफाई हेतु मनरेगा में कोई पैसा नहीं है जिस कारण नहर की सफाई हम नहीं करा सकते है। इसको सिंचाई विभाग स्वयं करवायेगा। फिर महिलाओं ने सिंचाई विभाग को प्रार्थना पत्र दिये लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई हार थक कर महिलाओं ने एक दिन पानी पंचायत की बैठक में तय किया कि ऐसे हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों कि हम लोग एक दिन अपनी पानी की समस्या को लेकर रोड जाम कर दें। और उसे तब तक न खोले जब तक हमारी समस्या के समाधान का काई नेता या जिला स्तर का अधिकारी आकर आश्वासन न दे। इसके बाद अपने पूर्व योजना के अनुसार दिनांक 05 दिसम्बर 2011 को माधौगढ़ रामपुरा रोड पर महिलाओं ने जाम लगा दिया। जिसमें गांव की एक सैकड़ा से अधिक महिला पुरूषों के अलावा ब्लाक प्रमुख श्री सुदामा दीक्षित ने भी गांव के लोगों का साथ दिया। जाम लगने से पूरा यातायात प्रभावित हो गया। जाम की सूचना पाकर थानाध्यक्ष रामपुरा ने मौके पर पहुँचकर जाम खुलवाने की कोशिश की लेकिन वह संगठन की महिलाओं के हौसले को डिगा नहीं सकें जिसमें पुलिस व महिलाओं में जमकर छीना झपटी हुई। पुलिस ने महिलाओं के अभद्रता की। जिसकी ब्लाक

प्रमुख ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात कर पुलिस द्वारा किये गये अभद्रता की शिकायत की। इसकी सूचना मिलते ही बसपा के राज्य सभा सांसद बृजलाल खाबरी ने मौके पर पहुँचकर 24 घंटे के अन्दर माइनर की सफाई करवाकर पानी दिलवाने का भरोसा दिलवाया इसके बाद जाम खोला गया। शाम को उपजिलाधिकारी माधौगढ़ ने ब्लाक प्रमुख की मौजूदगी में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत से खुदवाने का आदेश दिया गया। एक सप्ताह में ग्रामीणों को पानी मिल गया। अपनी हरी भरी फसल देखकर गांव वाले खुश है। गांव के उदयवीर का कहना है कि अब हम लोगों को अपनी आजीविका के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

जल सहेलियों की पहल से हुई हैण्डपम्प की स्थापना

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सरीला का गांव जलालपुर बेतवा नदीं के किनारे बसा हुआ है। इस गांव में कुल घरों की संख्या 320 है कुल जनसंख्या 2185 है तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या 553 है। गांव में पेयजल के लिए 40 हैण्डपम्प है गर्मी के मौसम में लगभग 20 हैण्डपम्प सूख जाते है। गांव में पेयजल आपूर्ति स्कीम भी स्थापित है मगर तकनीकी एवं कार्य गुणवत्ता खराबी के कारण वह जब से बनी कभी चलाई नहीं गई जिस कारण लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। जबकि इस गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के मुहल्ले में पेयजल स्रोतों की बहुत कमी थी इसलिए यह वर्ग

गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से अधिक प्रभावित था। इस दौरान परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा इस क्षेत्र में महिलाओं की पानी पर प्रथम हकदारी परियोजना के अर्न्तगत अप्रैल 2011 से कार्य करना प्रारम्भ किया। उस समय इस गांव मुें पानी की समस्या तो गंभीर थी लेकिन गांव के लोग इस समस्या का समाधान कैसे हो यह नहीं समझ पा रहे थे। संस्थान द्वारा इस गांव में गठित पानी पंचायत की मीटिंग में गांव की पानी की समस्या पर बार-बार चर्चा तो होती थी लेकिन इस लड़ाई की अगुवाई के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। एक दिन बैठक में पानी पंचायत की अध्यक्ष ज्ञानेश्वरी देवी पूरे गांव में विशेषतौर पर दलित वस्ती में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी 24 अन्य संगठन की सदस्यों के साथ मिलकर पहल करने को तैयार हो गयी। और इन लोगों ने दलित वस्ती में एक हैण्डपम्प स्थापित कराने तथा पेयजल आपूर्ति स्कीम का पानी अनुसूचित जाति में पहॅुचाने एवं स्टैण्ड पोस्ट स्थापित कराने की चर्चा की उसी दौरान सरकार से हर ब्लाक में आपातकालीन योजना के अर्न्तगत 50-50 हैण्डपम्प स्थापित कराने की घोषणा की गयी। इसके बाद ज्ञानेश्वरी देवी ने पानी पंचायत सदस्यों के साथ सामूहिक रूप से हैण्डपम्प स्थापना की मांग की तथा उपजिलाधिकारी सरीला से पेयजल योजना के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग मुहल्ले में पानी पहॅुचाने तथा स्टैण्ड पोस्ट स्थापित करवाने के लिए ज्ञापन दिया। संस्था के द्वारा 20 नये हैण्डपम्प स्थापित करवाने के लिए खण्ड विकास अधिकारी सरीला को सूची सौपी गई। इस पहल से ज्ञानेश्वरी की मांग

पर हैण्डपम्प स्थापित हुआ है। इससे 10 अनुसूचित जाति के परिवारों के 64 व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हुआ। अब ज्ञानेश्वरी सहित पूरा पानी पंचायत के सदस्य दलित मुहल्ले के लोग खुश है।

पानी प्रबंधन के लिए आगें आयीं जल सहेलियां

आज महिलाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता पानी, सबसे बड़ी समस्या बनी हुयी है। गॉव में महिलाओं की असल जिन्दगी प्रतिदिन पानी की व्यवस्था से शुरू होती है और पानी पर ही खत्म होती है। जिन्दगी का एक बड़ा हिस्सा पानी की व्यवस्था बनाने में कुर्बान करने वाली महिलाओं का चल, अचल सम्पत्ति में तो ठीक, पानी पर ही अपना हक नहीं है। इस विसंगति से निपटने के लिये परामर्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा अप्रैल 2011 से तालबेहट विकास खण्ड की 20 ग्राम पंचायतों में पानी पर महिलाओं की प्रथम हकदारी परियोजना के अन्तर्गत कार्य करना प्रारम्भ किया गया। जिसके अर्न्तगत गॉव में खुली बैठकें आयोजित कर चर्चा तथा गांव में पानी की समस्या से निपटने के लिए महिलाओं को संगठित कर पानी पंचायत का गठन किया गया। भले ही इस क्षेत्र में महिलाओं की अलग-अलग समस्या हो, लेकिन पानी की समस्या को वह प्राथमिकता देती है और इससे निपटने के लिए भी महिलाऐं आतुर दिख रही है। यहां 20 पंचायतों के 40 ग्रामों में अब तक 34 ग्रामों में संगठन बनाया गया है। इस समितियों की

महिलायें संगठित होकर अपने गांव की स्थिति परिस्थिति का विश्लेषण कर रही है तो कहीं श्रमदान, सामूहिक रूप से जनपहल प्रारम्भ कर चुकी है। अधिकांश समितियों में संस्थान कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनके द्वारा समिति की नियमावली तैयार की गयी है। गांव की समस्या के हिसाब से भले ही 19-20 सही लेकिन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी जनपहल सभी समितियों के अन्दर देखी जा सकती है। जिसके क्रम में परियोजना क्षेत्र के 5 गांव बुढ़ावनी, शाहपुर, जमालपुर, असऊपुरा ऐसे गांव है जहां की संगठन ने अलग से अपनी नियमावली तैयार की है, उसी के हिसाब से समय निर्धारित तिथि के अनुसार बैठक कर अपने क्षेत्र की समस्याओं का विश्लेषण कर नीतिगत पैरवी के आधार पर उसके समाधान के प्रयास किये जा रहे है। जिसके तहत बुढ़ावनी गांव में श्रमदान कर अन्य गांवों में बने तालाबों के संरक्षण के लिए पंचायत से लिखित में अनुरोध किया गया है। इसके आलावा पानी पंचायत की पहल पर परिवार एवं मानक को दृष्टिगत रखते हुये हैण्डपम्प की स्थापना, खराब पड़े हैण्डपम्प के रीबोर एवं मरम्मत के लिये प्रयास किये गये है। इन प्रयासों में भले ही सफलता केवल हैण्डपम्प की मरम्मत भर रही है। लेकिन एकजुट प्रयास से उनके संगठन को मजबूत आधार मिला है। इसके अलावा अन्य पांच गांव ककड़ारी, कोटरा, कलोथ्रा, चन्द्रापुर, थाना गांव की समितियों द्वारा अपने-अपने गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मजदूरी का समय से भुगतान न होना, समूह लोन में सेवा शुल्क आदि के समाधान के लिए पहल शुरू कर दी है।

संगठन की मजबूती के लिये नियमित बैठक कर पहल की जा रही है एवं समिति प्रतिनिधियों, जल सहेली को अन्य महिलाओं के जुड़ाव, नियमावली एवं समिति सुदृढ़ता के लिये प्रयास किये जा रहे है। साथ ही शेष ग्रामों में व्यक्ति संपर्क, लक्ष्य समुदाय का चिन्हांकन विपेज प्रोफाइल, घरेलू प्रपत्र, आर्थिक वर्गीकरण, संसाधन एवं सामाजिक मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है। आगामी समय में सभी गांवों की समितियों को उनकी मजबूती, नेटवर्किंग, केडर निर्माण कर ब्लांक स्तर पर एक बड़े संगठन की योजना है।

पानी की समस्या को लेकर जल सहेलियों ने की डीएम से शिकायत

हमीरपुर जनपद के विकास खण्ड सरीला का गांव पचखुरा है। जिसकी ब्लाक मुख्यालय से दूरी 8 किमी0 है। इस गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। यहां के लोगों के पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने यहां तीन वर्ष पहले एक पानी की टंकी का निर्माण तो करा दिया लेकिन इस टंकी से पानी का सही वितरण न हो पाने के कारण यहां के लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या जस की तस बनी रहीं । पानी की इस गंभीर समस्या से यहां के लोग जूझते तो रहे लेकिन कभी गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर कोई पहल नहीं की। इस गांव में पेयजल स्कीत के तहत 55 कनेक्शन किये गये जिसमें से 18 कनेक्शन दलित बस्ती के ऐसे हैं जिनमें कभी पानी ही नहीं पहुंचा और बाकी घरों में पानी तो पहुंचा लेकिन अधिकतर समय टंकी बंद रहने के कारण पानी

पानी की समस्या से उन्हें भी कोई बहुत राहत नहीं मिल रही थी। इस योजना में इस गांव के अलावा मनकहरी गांव भी लगता है। लेकिन इस गांव में एक भी कनेक्शन नहीं किये गये। परमार्थ समाज सेवी संस्थान द्वारा पानी पर महिलाओं की प्रथम हकदारी परियोजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में काम करना प्रारम्भ किया तो अपनी परियोजना क्षेत्र में इन गांवों को भी शामिल किया गया। जब संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा इन गांवों में मीटिंग की गई तो यहां पीने के पानी की गंभीर समस्या निकलकर आयी। इतनी बड़ी समस्या के बावजूद गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर जिला स्तर की बात दूर ब्लाक स्तर तक ले जाने को तैयार नहीं था। इसके बाद यहां सर्वप्रथम महिलाओं के संगठन को तैयार किया गया जिसे नाम दिया गया पानी पंचायत। पानी पंचायत के सदस्यों के साथ नियमित बैठक व मीटिंग कर उन्हें यह एहसास कराने की कोशिश की गई कि पानी आपका मौलिक अधिकार है जिसे आपसे छीना जा रहा हैं यदि इसके लिए आप लोग पहल नहीं करेंगे तो इस समस्या से निजात नहीं मिल सकती। इसके अलावा साफ सफाई व पानी प्रबंधन व उसके संरक्षण तथा परम्परागत से निजात नहीं मिल सकती। इसके अलावा साफ सफाई व पानी प्रबंधन व उसके संरक्षण तथा परम्परागत जल स्रोतों को जिंदा रखने जैसे जानकारी पानी पंचायत सदस्यों के साथ रोजाना बैठक के दौरान की जाती थी। धीरे-धीरे इसका असर दिखना शुरू हुआ और सर्वप्रथम संगठन की 15 महिलाओं ने एक साथ मिलकर ग्राम प्रधान को और इसके बाद उपजिलाधिकारी सरीला को ज्ञापन देकर गांव में पानी की समस्या से अवगत कराया। यहां तक आते-आते इन महिलाओं

का हौसला इतना बढ़ गया कि वह अब अपने गांव की समस्या को लेकर किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हो गयी। इसी तरह परियोजना क्षेत्र के अन्य गांव बरगुवां में भी पानी की बेहद गंभीर समस्या थी। वैसे तो यहां 14 हैण्डपम्प स्थापित हैं लेकिन पिछले एक वर्ष से इनमें से 12 हैण्डपम्प खराब हैं जिससे पूरे गांव में पानी की समस्या है। उपरोक्त दोनों गांवों में पानी की समस्या का हल न होते देख दिनांक 29 सितम्बर 2012 को पानी पंचायत की सदस्य महिलाओं ने हमीर पुर की जिलाधिकारी श्रीमती वी चन्द्रकला को ज्ञापन देकर पिछले काफी दिनों से जूझ रहीं पानी की समस्या से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने पानी पंचायत की महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए महिलाओं की मौजूदगी के समय ही मुख्य विकास अधिकारी श्री राम निवाज को बुलाकर इन गांवों की समस्या के समाधान के लिए निर्देंषित किया तथा कहा कि इन गांवों की समस्या के समाधान के लिए एक सप्ताह में कार्य शुरू कर दिये जायें। जिलाधिकारी से मिलकर पानी पंचायत की महिलाये बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि अब हम लोग अपने गांव में कोई भी समस्या नहीं रहने देगें।

हमीरपुर जिले के पारछा ग्राम की जल सहेली कुन्ती देवी कहती है कि हमारा गांव पानी की कमी से काफी समय से जूझ रहा था। जिला मुख्यालय पर हमनें ज्ञापन दिये और लगातार पैरवी की अब हैण्डपम्प भी है और बोरिंग भी। अब पानी लाने की दूरी कम हो गई है। पहले 2 किमी0 तक पानी लाने जाना पड़ता था। ऐसे अनेको उदाहरण है जिसमें महिलायें पूरी लड़ाई

की आगवनी कर रही है और सारी सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई लडने के लिये बाहर आई है।

सरीला ग्रांम की जल सहेली ललिता देवी कहती है कि पहले से अब बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले लोग घरों के बाहर कूड़ा -करकट डाल देते थे अब वे जागरूक हो गये है। गंदगी को होने वाली बीमारियों के उसे अब वे जागरूक हो गये है। वे कहती है कि पानी की समस्या को लेकर हम डी0एम0 से मिले और ज्ञापन दिया। एस0डी0एम0 से भी मिले, उन्होंने 1000 :पये का चंदा भी दिया और सहयोग का अश्वासन भी जब पंचायत को तालाब की सफाई के लिये मदद नहीं की तो यही रास्ता अपनाया गया और सफलता भी मिली।महिलाओं के आगे आने से न केवल उनकी सामाजिक स्थितियां बदली है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास का भाव भी जागृत हुआ है यही हमारी सफलता की शुरूआत है। ललिता देवी कहती है कि पहले सें अब बहुत बदलाव देखने को मिल रहा हैं पहले लोग घरों के बाहर कूड़ा करकट डाल देते ये अब नही डालते है। अपनी समस्याओं को लेकर हम एक समूह में डीएम से मिले और ज्ञापन दिये। एस0डी0एम0 से मिले और उन्होने एक हजार रूपया चन्दा भी दिया। जब पंचायत ने तालाब की सफाई के लिये मदद नही की तो यही रास्ता अपनाया और सफलता मिली।विनीता कहती है कि जल की समस्या गम्भीर है अक्सर पानी के लिये आपस में झगड़ा भी होता है। पानी के नलों को लोग इस्तेमाल नहीं करने देते हैं 130 :0 महीना पानी

के लिये लेते है। पानी भरने के लिये 2-2 घण्टे नल पर इन्तजार करना पड़ता है। पानी की नालियों को लेकर भी झगड़ा होता है। लेकिन हम इस पर जल्द ही कर लेंगे। कहती है जबसे चेक डैम बना है जानवरो को पानी की समस्या खत्म हो गई। शौचायल की समस्या सबसे बड़ी है। अभी कुछ दिन पहले एवं महिला की हत्या हो गई तब से महिलाये सुबह 8 बजे से पहले नही जाती और शाम चार बजे के पहले लौट आती है मनकारी से पाइप लाइन लगी थी वो टूट गयी थी। जल सहेलियों ने मिलकर उसे बना दिया।

कुन्ती देवी का कहना है कि पानी लाने की दूरी कम हो गई है पहले 2 किमी0 जाना पड़ता था। अब हैण्डपम्प भी है और बोरिंग भी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिये लगातार पैरवी की तब जाकर काम हुआ कुऐं सूखें पड़ें है। 7 कुऐं सूखे है हमें ही कुछ करना होगा।

कुंती देवी का यह विश्वास बताता है कि बुंदेलखंड कि जल सहेलियां परिवर्तन कि नयी प्रतीक बन गयी हैं. घूँघट कि ओत से निकल कर उन्होंने अपने भविष्य निर्माण कि बागडोर अपने हांथों में ले ली हैं. जिंदगी कि मुश्किलों को संगठन कि मजबूती और और अपने दृढ निश्चय से उन्होंने आसान कर लिया है. बुंदेलखंड के इतिहास में जल सहेलियों ने अपने लिए सुनहरे पन्नों को सुरक्षित कर लिया है और अब वे अपने गाँव से निकल कर पुरे इलाके कि तस्वीर बदलने में लगी हुयी हैं

बुन्देलखण्ड में जल सहेलियाँ अपने हक व अधिकारो की लड़ाई लड़ रही है

बुन्देलखण्ड अपनी सामन्तवादी व्यवस्था के लिए विख्यात है। आज भी आजादी के 65 साल बाद इस इलाके में जातिगत भेदभाव के साथ महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार है। बुन्देलखण्ड के ललितपुर जिले में सामन्ती व्यवस्थाएँ इतनी मजबूत है कि उनके चलते कमजोर तबके और महिलाओं को कई तरह की परेषानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले दो वर्शों में ललितपुर के तालबेहट ब्लाक में पानी की उपलब्धता के लिए गाँव गाँव में तैयार हुई जल सहेलियाँ अपने हक अधिकारों के लिए प्रयासरत है। अभी हाल में ही ललितपुर जिले के ग्राम कलोथरा में मानव अधिकार आयोग की टीम गाँव में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और मानव अधिकारों के उल्लंघन की हालत जानने पहुँची तो वहाँ की जल सहेलियाँ रामवती, गनेषी व संगीता ने अपने गाँव की हालातों को टीम के सामने रखा तो हालात बद से बद्तर निकले। गाँव मे पीने के पानी के लिए सिर्फ दो हैण्डपम्प है, कुँओं का पानी पीने योग्य नही है। गाँव में षौचालय नही है। सरकारी योजनाएँ गाँव तक पहुँच नही रही है। ऐसे कठिन हालातों में ग्रामीणजन अपना जीवन व्यतीत कर रहे है। गाँव की हालत देखकर मानव अधिकार आयोग से आए श्री एस0एन0 पाण्डेय तथा राजबीर सिंह हालात देखकर दंग रह गए। जल सहेलियों ने बिना किसी डर, भय व दबाव के अपनी समस्याएँ रखी जिस पर आई टीम ने प्रषासनिक अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए निर्देषित किया। साथ ही निर्देष दिया कि जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव को रोका जाए। कल तक जहाँ महिलाएँ दबाव के कारण घर से नही निकलती थी, आज जल

सहेलियाँगाँव गाँव में महिला पानी पंचायत के माध्यम से महिलाओं को संगठित करने का कार्य कर रही है। ललितपुर के 40 गाँवों में 40 ग्राम स्तरीय पानी पंचायत तथा 84 जल सहेलियाँ तैयार हो गई है।

जल सहेली द्वारा किये गये प्रयास

यद्यपि जल सहेली की अवधारणा बुन्देलखण्ड में पानी की समस्या के उद्देश्य के साथ की गयी थी। लेकिन धीरे धीरे जल सहेलिया गाँव के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभा रहीं हैं। पानी के अलावा इनके द्वारा अन्य क्षेत्रो में क्ये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार हैं।

क्रम	जल सहेलियो द्वारा किये गये प्रयास	लाभान्वित ग्राम सभाये
1	ग्राम सभा की बैठको में भाग लेने के लिये महिलाओ को जागरूक और प्रेरित करना	ग्राम सरीला विकास खण्ड के 6 ग्राम सभाओ, तालबहेट विकास खण्ड के 7 ग्राम सभाओ में महिलायें निरन्तर न केवल ग्राम सभा की बैठको में भाग ले रही है बल्कि अपना सक्रिय योगदान भी दे रहीं हैं।
		जल सहेलियो की प्रेरणा से सरीला विकास खण्ड में महिलाओ ने पहली बार मनरेगा के तहत विभिन्न अधिकारो के लिये जागरूक किया
		धमना गाँव की जल सहेली श्रीमती सीमा देवी ने 17 महिलाओं को मनरेगा के तहत कार्य माँगने के लिये प्रेरित किया
		कलोतरा गाँव की जल सहेली श्रीमती रमावती ने 16 जाब कार्ईधारी महिलाओं

		को बैंक खाता खोलने के लिये प्रेरित किया और खाता खोलने में सहायता की।
		जल सहेलियो की प्रयासों से सरीला विकास खण्ड के कुँअरपुरा गाँव में 12 जाब कार्ईधारी महिलाओं को 17,500 रूपये के बकाया मजदूरी का भुगतान किया गया।
		सरीला विकासखण्ड डौरा गाँव मे 60 जाब कार्ईधारी महिलाओं को 6 दिन का कार्य मिला
		सरीला विकासखण्ड में ही 1,60,000 रूपये के लम्बित मजदूरियों का भुगतान किया गया।
		जल सहेलियो के प्रयासो से इन गाँवों में पंचायत रोजगार सेवकों द्धारा कार्य के लिये किये गये आवेदनो की पावती दी जाने लगी है
		40 जाब कार्ईधारी महिलाओं को 33,000 रूपये के लम्बित मजदूरियों का भुगतान किया गया।
		जलालपुर, छिबौली, वीरपुर और हरसौरी गाँवो में जाब कार्ड प्रधानो से वापस लिये गये, जिसे अब लाभान्वित परिवार स्वयं रखते हैं।

		ललितुर जिले के कलुथरा, शाह्पुर, बुधवारी, ऊदगाँव और बम्हौरी, गाँवो में कार्यो के लिये आवेदन को स्वाकार किया जाने लगा है।
		जलौन जिले के कस्बा गाँव में 21 जाब काईधारी महिलाओं को बी0डी0ओ0 द्वारा कार्य मुहैया कराया गया तथा सात दिनो के अन्दर इन्हे मजदूरी का भुगतान भी किया गया।
2	वद्धावस्था पेन्शन	जालौन जिले के धम्मा गाँव की जल सहेली श्रीमती सीमा देवी द्वारा 3 परिवारो को वृद्धावस्था पेन्शन दिलाने में सफलता पूर्वक सहायता की गई।
		कलोथरा गाँव की जलसहेली श्रीमती रमावती द्वारा 01 परिवार को वृद्धावस्था पेन्शन के नवीनीकरण में सफलता पूर्वक सहायता की गई।
3	विधवा पेन्शन	कलोथरा गाँव के एक परिवार को विधवा पेन्शन के दिलाने में सफलता पूर्वक सहायता की गई।
4	सार्वजनिक वितरण योजना	तालबेहट विकास खण्ड के धव्वा और अतरौली गाँवो मे सार्वजनिक वितरण योजना की दुकानो को सुचारू रूप से चलावाने के लिये सफलतापूर्वक प्रयास किये गये।
5	मध्यान्ह भोजन	के हैदल्पुर, निनवाली जागीर और

	योजना	जाजेपुरा गाँवो में मध्यान्न भोजन योजना सुचारू रूप से चलावाने के लिये सफलतापूर्वक प्रयास किये गये।
6	सडक निर्माण	तरूली ग्राम जालौन की जल सहेली श्रीमती राजकुमारी के प्रयासों से गाँ की दलित बस्ती में ग्राम प्रधान द्वारा आर0सी0सी0 सडक का निरंआण कराया गया।
7	रसोई बागवानी का आरम्भ	सरीला विकास खण्ड के हरसूरी गाँव के 06 और अतरौली के 02 परिवारों ने जल सहेली श्रीमती ललिता की प्रेरणा से रसोई बागवानी का निर्माण किया है।
		हैदलपुर की जल सहेली श्रीमती माधुरी देवी की प्रेरणा से गाँव के 13 परिवारों ने रसोई बागवानी का निर्माण किया है।
8	पानी के स्रोतो की सफाई	उनके पास चबूतरे के निर्माण के लिये श्रमदान ह्य सरीला विकासखण्ड के जलालपुर गाँव की जल सहेली श्रीमती सरितादेवी की प्रेरणा से 20 ग्रामीण ों मे पानी के स्रोतो के पास चबूतरे के निर्माण के लिये श्रमदान किया।
		तिहाड गाँव की जल सहेली श्रीमती सरिता देवी की प्रेरणा से तालाब की

		सफाई की गयी।
		धरोपुर गाँव की जल सहेली श्रीमती कमलेश कुमारी की प्रेरणा से 26 महिलाओ ने ताला ब की सफाई के लिये श्रमदान किया
		असपुरा गाँव की जल सहेली श्रीमती सरोज की प्रेरणा से 32 महिलाओं ने नहर की सफाई के लिये श्रम्दान किया
9	आजीविका	मामना गाँव की जल सहेली श्रीमती कुन्ती देवी द्वारा सिलाई के व्यावसायिक कार्य का आरम्भ किया गया।
10	महिलओ के साथ भेदभाव	कलोथरा गाँव की जल सहेली रमावती द्वारा महिला अधिकारो और उनके साथ भेदभाव के खिलाफ अनेक बार कार्यवाही की गयी।
11	बालिकाओ की जागरूकता	अस्पुरा गाँव की जल सहेली बबली द्वारा बालिका समूह की स्थापना और उनमें व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वास्थ्य को लेकर प्रेरणादायी जागरूकता कार्यकर्म चलाया गया।
12	एकीकृत बाल कल्याण योजना के लिये जागरूकता	असपुरा गाँव की जल सहेली बबली द्वारा एकीकृत बाल कल्याण योजना के सम्बन्ध में अपने गाँ में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया।
13	शिक्षा के लिये	बढ़ौनी गाँव की जल सहेली सुनीता

	जागरूकता	द्वारा गाँव में बच्चो की शिक्षा के लिये अनेक माता पिता को जागरूक किया गया
		पचकौरा गाँव की जल सहेली लक्ष्मी द्वारा पानी पंचायत की सदस्यो हस्ताक्षर करना सिखाया गया।
		पचकौरा गाँव की ही जल सहेली सरस्वती देवी द्वारा 10 महिलाओ को हस्ताक्षर सिखाया गया तथा उन्हे पढने के लिये प्रेरित किया गया।
14	वृक्षारोपण	बढौनी गांव की जल सहेली सुनीता द्वारा गाँव की महिलाओ को वृक्षारोपण के लिये प्रेरित किया गया तथा पेड लगाये गये।
15	महिला सशक्तीकरण	एटा गाँव की जल सहेली फरीदा बेगम की प्रेरणा से अनेक महिलाओं ने स्वँय सहायता समूह और श्र।प्ब। कार्यक्रम के उपभोक्ता समूह की सदस्यता ली है ।
16	क्लोरीनीकरण	चन्दा गाँव की जल सहेली राजकुमारी के प्रयासो से गाँव में पानी का नियमित शोधन किया जाता है।
17	स्वास्थ्य एवँ स्वक्षता कार्यक्रम	धम्न गाँव की जल सहेली सीमा देवी द्वारा गाँ में निरन्तर स्वास्थ्य एवँ स्वक्षता कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

प्रकाशक
परमार्थ समाजसेवी संस्थान